AMAR UJALA 6 JULY, 2019

यमुना समेत 11 नदियों को निर्मल बनाने के लिए मंथन

एफआरआई में आयोजित सेमिनार में नदियों की बदहाली पर जताई चिंता

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। गंगा को निर्मल, अविरल बनाने को लेकर शुरू की कवायद के बीच अब केंद्र सरकार ने यमुना समेत देश की 11 और प्रमुख निदयों को स्वच्छ, निर्मल बनाने के साथ ही पुनर्जीवित करने की पहल की है। केंद्रीय बन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश पर वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) के वैज्ञानिकों ने परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। सभी वैज्ञानिकों ने निदयों के किनारे अधिक से अधिक पेड़ लगाने और आमजन को इसके प्रति जागरूक करने की बात कही।

वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) में शुक्रवार का एक दिवसीय वैज्ञानिक सेमिनार का आयोजन किया गया। संस्थान के निदेशक एएस रावत ने यमुना समेत 13 प्रमुख नदियों को स्वच्छ बनाने की दिशा में अब तक किए प्रयासों की जानकारी दी। कहा कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

परियोजना में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां भी शामिल

परियोजना समन्यवक डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि परियोजना में यमुना नदी के अलावा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब और झेलम जैसी नदियों को भी शामिल किया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

नदियों के किनारे पेड़ लगाने और लोगों को जागरूक करने पर दिया जोर

वानिकी मध्यस्थता के जिरए 13 बड़ी निदयों के पुनरोद्धार का कार्य कर रही है। वानिकी मध्यस्थता के जिरए यमुना के पुनरोद्धार की डीपीआर का कार्य मार्च 2020 तक तैयार कर लिया जाएगा। 30 सितंबर 2020 तक इसे मंत्रालय को सौंपा जाएगा।

उप महानिदेशक डॉ. एसडी शर्मा ने निदयों को साफ सुथरा बनाने को लेकर इस्तेमाल की जा रही तकनीकों के बारे में बताया। इससे पूर्व परियोजना के को निदयों का अध्ययन करने और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिषद के नौ क्षेत्रीय संस्थानों को अलग-अलग निदयों का अध्ययन करने और उनकी रिपोर्ट तैयार करने जिम्मेदारी सौंपी गई है।



समन्वयक डॉ. दिनेश कुमार ने परियोजना के बारे में जानकारी दी। सेमिनार को पूर्व प्रमुख वन संरक्षक डॉ. आरबीएस रावत, वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक मोनिष मिल्लक, मुख्य वन संरक्षक जीसी पांडे, आईआईटी रुड़की, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रुड़की, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, मृदा संरक्षण, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों ने संबोधित किया।

DAINIK BHASKAR 6 JULY, 2019

यमुना नदी के बचाव को लेकर बैटक आयोजित, बनाई रणनीति



यमुना नदी के पुनरुद्धार को लेकर आयोजित बैठक में विचार रखते वक्ता।

छाया-भास्कर

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। एफआरआई ने शुक्रवार को राज्य के लिए वानिकी मध्यस्थता के जिरए यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए उत्तराखंड राज्य के साथ पहली एक दिवसीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के प्रारंभ में परियोजना समन्वयक डॉ. दिनेश कुमार ने परियोजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इसके बाद निदेशक एएस रावत ने प्रतिनिधियों को यमुना को स्वच्छ बनाने की दिशा

एएफआरआई में एक दिवसीय परामर्श बैठक का आयोजन

में किए गए प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उप महानिदेशक (अनुसंधान) एसडी शर्मा ने भी विभिन्न नई तकनीकों द्वारा सभी प्रमुख निदयों को कैसे साफ किया जाए विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।

उत्तराखंड वन निगम के एमडी मनीष मुलिक ने यमुना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार

करने में वानिकी मध्यस्थता का विवरण दिया तथा उन्होंने परियोजना की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दीं। विभिन्न विशेषज्ञों ने यमुना सफाई पर तीन तकनीकी सत्रों में जैसे गंगा सफाई के प्रयासों से प्राप्त किए गए अनुभव और भविष्य की संभावनाएं, वानिकी हस्तक्षेप, सामुदायिक भागीदारी मॉडल, कॉन्सल्टेशन. स्टेकहोल्डर प्रौद्योगिकी उपयोग और जीआईएस लेयरों की मापदंड की पहचान और पैनल चर्चा पर अपने विचार व्यक्त किए।

DAINIK JAGRAN 6 JULY, 2019

यंगा नदी की तर्ज पर शुरू किए जाएंगे यमना व उसकी सहायक नदियों में संरक्षण संबंधी कार्य, एफआरआइ को डीपीआर की जिम्मेदारी

मुना का 3.45 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल होगा संरक्षित

जागरण संवाददाता, देहरादुन: उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा नदी के बाद अब यमुना के संरक्षण की दिशा में भी वहद स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके लिए यमुना नदी के संरक्षण को वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने की जिम्मेदारी मिली है। एफआरआइ ने भी इस दिशा में प्रयास तेज करते हुए पहली एक दिवसीय परामर्श बैठक का आयोजन किया। तमाम विशेषज्ञ संस्थानों ने इसका हिस्सा बनकर डीपीआर तैयार करने को लेकर सुझाव दिए।

शक्रवार को एफआरआइ के दीक्षांत सभागार एफआरआइ के निदेशक एएस रावत ने परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। मार्च 2020 तक डीपीआर तैयार कर संस्थान के मुख्यालय भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है। खासकर संरक्षण को लेकर वानिकी (आइसीएफआरई) को सौंपी जानी है। के लिए यह डीपीआर तैयार की जा रही

यमना नदी बेसिन में इस तरह बढा दबाव (आजादी के बाद)

- आबादी का दबाव 3.5 गुना हुआ।
- सिंचाई की मांग दो गुनी हुई।
- नदी बेसिन क्षेत्र में भजल दोहन तिगुना हुआ।
- आजादी के समय सतह वाले जल का दोहन 60 फीसद व भजल दोहन २० फीसद था।
- वर्तमान में भूजल दोहन 57 फीसद हो गया, जबकि सतह वाले जल का दोहन 37 फीसद तक किया जा रहा।
- यमना व उसकी सहायक नदियों में जल प्रदूषण, खनन, गंदे पानी को उड़ेलने, इंडस्ट्री के गंदे पानी का दबाव आदि समस्याएं बढ रही हैं।



शुक्रवार को यमुना नदी के संरक्षण को लेकर एफआरआइ में आयोजित बैठक में मंचासीन अधिकारी • जागरण

उत्तराखंड का यमुनोत्री ग्लेशियर है यमुना का उदगम

यमुना नदी का उदगम उत्तरकाशी जिले के बंदरपंछ से होता है। हिमालयी घाटियों

में करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यमुना नदी चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर प्रयागराज (इलाहाबाद) में गंगा में मिल जाती है।

हिमालयी क्षेत्र में यह सहायक नदियां

ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, टौंस व गिरी।

यमुना नदी बेसिन क्षेत्र की स्थिति (वर्ग किलोमीटर)

राज्य	क्षेत्रफल	फीसद में
उत्तराखंड	3771	1.1
हिमाचल प्रदेश	5799	1.7
उत्तर प्रदेश	70437	20.4
हरियाणा	21265	6.1
राजस्थान	102883	29.7
मध्य प्रदेश	140208	40.6
दिल्ली	1485	0.4

मैदानी क्षेत्र में यह सहायक नदियां

हिंडन, चंबल, सिंद, बेतवा, केन आदि।

के माध्यम से उपाय तैयार किए जाएंगे। यहां से डीपीआर को केंद्र सरकार के सुपूर्व उन्होंने यह भी बताया कि गंगा नदी के किया जाएगा। यमुना नदी बेसिन के कुल संरक्षण की डीपीआर भी एफआरआइ ने सात राज्यों में काम किया जाना है और हैं और उनका समाधान किस तरीके से 3.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल. तैयार की थी और इसके आधार पर काम सभी जगह इस तरह की परामर्श बैठकों किया जा सकता है। बैठक में उत्तराखंड भी शुरू किए जा चुके हैं। वहीं, परियोजना

समन्वयक डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि विभागों से आए विशेषज्ञों ने बताया कि संरक्षण का कार्य यमुना की प्रमुख सहायक

यमुना व उसकी सहायक नदियों में किस निदयों में भी किया जाएगा। इसके तहत तरह दबाव बढ़ने से क्या दिक्कतें आ रही का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक

मोनीष मलिक, आइसीएफआरई के उप महानिदेशक एसडी शर्मा समेत आइआइटी रुड़की, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आइआइआरएस), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (एनआइएच) आदि के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

GARHWAL POST 6 JULY, 2019

FRI holds consultations on Yamuna Rejuvenation

By OUR STAFF REPORTER DEHRADUN, 5 Jul: Forest Research Institute organised a one-day 'First Consultation Meeting of Uttarakhand on DPR Preparation for Rejuvenation of Yamuna River through Forestry Interventions' for the State, today, at its Convocation Hall, here.

The meeting was organised under the project sanctioned by ICFRE and MoEFCC. Experts from IITs, National Institute of Hydrology, Indian Institute of Remote Sensing, Soil Conservation, State Forest Department of Uttarakhand, Pollution Control Board and NGOs participated in the meeting and



deliberated on the project formulation and implementation, and identified the opportunities and constraints to make the Yamuna clean.

At the outset, Dr Dinesh Kumar, Scientist G & Project Coordinator,

welcomed the dignitaries and stakeholders. He briefed them on the project. AS Rawat, Director, FRI, provided participants details about efforts to be made to make the Yamuna clean. He also mentioned

the various polluting activities along the river. SD Sharma, DDG (Research), ICFRE, said that his organisation had been assigned the task of rejuvenating 9 major rivers of India by using new technologies. He said that the DPR of Yamuna Rejuvenation through Forestry Interventions would be prepared by March 2020.

Monish Mullick, MD, Uttarakhand Forest Development Corporation, mentioned the details of forestry intervention for the Yamuna. Various experts expressed their views on cleaning the Yamuna in three technical sessions - Experiences from Ganga Cleaning Efforts and Future Possibilities, Forestry Interventions, Community Participation Models, Stakeholder Consultation, Technology Usage and Criteria Identification of GIS layers and panel discussion.

GARH SANVEDNA 6 JULY, 2019



गंगा के बाद अब यमुना के संरक्षण की दिशा में भी वृहद स्तर पर प्रयास शुरू, डीपीआर तैयार करने को लेकर सुझाव दिए, एफआरआइ में परामर्श बैठक का आयोजन

देहरादून, (गढ़ संवेदना)। गंगा नदी के बाद अब यमुना के संरक्षण की दिशा में भी वृहद स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके लिए यमुना नदी के संरक्षण को वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने की जिम्मेदारी मिली है। एफआरआइ ने भी इस दिशा में प्रयास तेज करते हुए पहली एक दिवसीय परामर्श बैठक का आयोजन किया। तमाम विशेषज्ञ संस्थानों ने इसका हिस्सा बनकर डीपीआर तैयार करने को लेकर सुझाव दिए।

शुक्रवार को एफआरआइ के दीक्षांत सभागार एफआरआइ के निदेशक एएस रावत ने परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। मार्च 2020 तक डीपीआर तैयार कर संस्थान के मुख्यालय भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) को सौंपी जानी है। यहां से डीपीआर को केंद्र सरकार के सुपुर्द किया जाएगा। यमुना नदी बेसिन के कुल 3.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए यह डीपीआर तैयार की जा रही है। खासकर संरक्षण को लेकर वानिकी के माध्यम से उपाय तैयार किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि गंगा नदी के संरक्षण की डीपीआर भी एफआरआइ ने तैयार की थी और इसके आधार पर काम भी शुरू किए जा चुके हैं। वहीं, परियोजना समन्वयक डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि संरक्षण का कार्य यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में भी किया जाएगा। इसके तहत सात राज्यों में काम किया जाना है और सभी जगह इस तरह की परामर्श बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न विभागों से आए विशेषज्ञों ने बताया कि यमुना व उसकी सहायक नदियों में किस तरह दबाव बढ़ने से क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। बैठक में उत्तराखंड वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक मोनीष मलिक, आइसीएफआरई के उप महानिदेशक एसडी शर्मा समेत आइआइटी रुड़की, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आइआइआरएस), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (एनआइएच) आदि के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

HINDUSTAN TIMES 6JULY, 2019

YAMUNA REJUVENATION

'Mitigating soil erosion, stopping effluents key'

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

DEHRADUN: Major challenges in rejuvenating the Yamuna river are stopping flow of effluents into it and arresting soil erosion near it, experts said here on Friday.

Experts from different departments gathered at Forest Research Institute (FRI) here for "Consultation meeting for Uttarakhand in detailed project report (DPR) preparation for rejuvenation of Yamuna River through forestry interventions".

FRI has been tasked with preparing the DPR for Yamuna rejuvenation on the lines of Ganga rejuvenation by the Centre.

It has to submit the report by March 2020 for which it is studying the forestry intervention aspects in seven states -- Uttarakhand, Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh and Madhya Pradesh -- where the river flows.

Monish Mullick, managing director of Uttarakhand State Forest Development Corporation, said: "Yamuna is one of the important rivers flowing in north India on which millions of people are depended for various purposes." "The purity of Yamuna river remains intact till it flows in Uttarakhand after originating from Yamunotri in state."



Experts at the meeting in Dehradun on Friday.

НТ РНОТО

"As soon it enters plain areas it is no more a river but a sewage drain. Before rejuvenating it, one needs to first stop flowing of effluents into it and soil erosion," said Mullick, who was present at the meeting.

He said to rejuve nate the river, its "uninterrupted and unpolluted flow has to be assured".

Dinesh Sharma, project co-ordinator and scientist at FRI, said there were three areas "forest areas, cities and agricultural areas near the river where steps for rejuvenation are to be implemented".

"For the rejuvenation, plantation of indigenous species of shrubs, trees and plants, motivating farmers to stop use of fertilisers and pesticides, implementing

agro-forestry plantation models, implementing low-cost models for riverfront development and development of eco-parks could be recommended for the purpose," he said.

Sharma said, "Controlling invasive weeds and low-cost soil and moisture conservation models to stop the flow of silt in the river."

Terming the project an important one, FRI director Arun Singh Rawat said, "FRI has conducted meetings with departments concerned of UP, MP, Rajasthan and Himachal. Soon meetings would be held with Delhi and Haryana."

"FRI would engage the Wildlife Institute of India in coming days to discuss the steps for revival of Yamuna's ecosystem," he said.

THE HAWK 6 JULY, 2019

Consultation Meeting Of Uttarakhand Held



Dehradun: Forest Research Institute has organized the one-day First Consultation Meeting of Uttarakhand on DPR Preparation for Rejuvenation of Yamuna River through Forestry Inter-

ventions" for the State of Uttarakhand on 05 July 2019 at Convocation Hall, FRI, Dehradun. This meeting was organized under the project sanctioned by ICFRE/MoEFCC, Govt. India,

New Delhi. Experts from IIT's, National Institute of Hydrology, Indian Institute of Remote Sensing, Soil Conservation, State Forest Department of Uttarakhand, Pollution Control Board and NGO's have participated in the meetingand deliberated on the project formulation & implementation and identify the opportunities & constraints to make Yamuna clean.

At the outsetDr. Dinesh Kumar, Scientist G & Project Coordinator welcomed the dignitaries/stakeholdersand he apprised about of the project. Sh. A.S. Rawat, Director. **FRIinformedparticipants** details about efforts to be made in the directionmakingYamuna clean.He also mentioned about various polluting activities around river Yamuna.Sh. S.D. Sharma, DDG (Research), ICFRE told that ICFRE has assigned task of rejuvenation of 9 major rivers of India by performing various new

technologies by Govt. of India. He told that DPR of Yamuna Rejuvenation through Forestry Interventions will be prepared by March 2020.Sh. Monish Mullick, IFS, MD. UttarakhandForest Development Corporation mentioned the details of forestry intervention in preparation of detail project report for Yamuna and he also conveyed his best wishes for the success of project. Various experts explained their views on cleaning Yamuna in three technical sessions viz. Experiences from Ganga Cleaning Efforts and Future Possibilities, Forestry Interventions, Community ParticipationModels, Stakeholder Consultation, Technology Usage and Criterialdentification of GIS layers and panel discussion.

RASHRIYASAHARA 6 JULY, 2019

यमुनाः डीपीआर मार्च 2020 तक

सहारा न्यूज ब्यूरो

दहरादुन।

वन अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत कक्ष में शुक्रवार को वानिकी मध्यस्थता के जिए यम्ना नदी के पुनर्रद्वार के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्श बैठकं आयोजित की गई।

बैठक में आईआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑप हाइड्रोलाजी, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, मृदा संरक्षण संस्थान, उत्तराखंड वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही हितधारकों ने प्रतिभाग सबसे पहले वरिष्ठ वैज्ञानिक व परियोजना किया गया। समन्वयक डा. दिनेश कुमार ने प्रतिभागियों व हितधारकों का स्वागत किया। उन्होंने परियोजना के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक एएस रावत ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने की दिशा में किये गये प्रयासों के बारे में बताया। यमुना नदी को प्रदूषित करने वाले कारकों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के उप महानिदेशक (अनुसंधान) एसडी शर्मा ने बताया कि वानिकी मध्यस्था के जिएए आईसीएफआरई 13 छोटी-बड़ी नदियों के पुर्नरुद्वार का कार्य कर रही है। यमुना नदी का पुनरुद्वार करना भी इस परियोजना में शामिल है। बताया कि इस बावत मार्च 2020 तक डीपीआर तैयार की जानी है। उन्होंने यह भी बताया कि नई तकनीकों के माध्यम से संस्थान ने प्रमुख नदियों को कैसे स्वच्छ किया है।

उत्तराखंड वन विकास निगम के प्रबंध

डीपीआर तैयार करने के लिए विभागीय अधिकारियों, विषय विशोषज्ञों व हितधारकों की परामर्श बैठक

निदेशक मनीष मुलिक ने यमुना नदी के पुनरुद्वार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में वानिको मध्यस्थता का विवरण दिया। उम्मीद जताई कि यह परियोजना भी सफल रहेगी। वहीं बैठक में शिरकत कर रहे अन्य विषय विशेषज्ञों ने तकनीकी सत्र में भी अहम मुद्दों पर चर्चा की। किया। प्रतिभागियों ने परियोजना के क्रियान्वयन गंगा की सफाई के प्रयासों से प्राप्त अनुभव, व यम्ना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए विस्तार भविष्य की संभावनाएं, वानिकी हस्तक्षेफ, से विचार-विमर्श किया गया। परियोजना के सामुदायिक भागीदारी, स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन, क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों व इनका प्रौद्योगिकी उपयोग, जीआईएस आदि की समाधान करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में उपयोगिता व महत्ता पर भी विचार-विमर्श

SHAHTIMES 6JULY, 2019

एफआरआई में यमुना नदी के पुनरुद्वार को डीपीआर तैयार करने के लिए बैठक

शाह टाइम्स संवाददाता देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान ने उत्तराखंड राज्य के लिए वानिकी मध्यस्थता के जिरए यमुना नदी के पुनरुद्धार को डीपीआर तैयार करने के लिए उत्तराखंड राज्य के साथ पहली एक दिवसीय परामर्श बैठक का आयोजन किया।

यह बैठक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना के तहत आयोजित की गई है। इस बैठक में आईआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, मृदा

2020 तक तैयार होगा डीपीआर का कार्य

संरक्षण, उत्तराखंड राज्य वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सहित विशेषज्ञों और हितधारकों ने भाग लिया तथा परियोजना के सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन तथा यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए अवसरों एवं बाधाओं की पहचान के लिए विचार. विमर्श किए। बैठक के प्रारंभ में डॉ. दिनेश कुमार, वैज्ञानिक जी एवं परियोजना समन्वयक ने सभी का स्वागत किया तथा परियोजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। निदेशक

एफआई ने प्रतिनिधयों को यमुना को स्वच्छ बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में बताया तथा उन्होंने यमुना नदी के चारों ओर विविध प्रदूषण कार्यकलापों के बारे में भी जिक्र किया। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् वानिकी मध्यस्थता के जरिए 13 बडी नदियों को प्नरूद्वार का कार्य कर रही है। उन्होने यह भी बताया कि वानिको मध्यस्थता के जिए यम्ना के पुनरूद्धार को डीपीआर का कार्य मार्च, 2020 तक तैयार कर लिया जाएगा। बैठक में डॉ. एसडी शर्मा, वन निगम के एमडी मोनीष मल्लिक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

THE PIONEER 6 JULY, 2019

FRI holds consultations on cleaning Yamuna through forestry

PNS DEHRADUN

The Forest Research Institute (FRI) held a day-long first consultation meeting of Uttarakhand on detailed project report preparation for rejuvenation of Yamuna river through forestry interventions for the State of Úttarakhand on Friday. This meeting was organised under the project sanctioned by Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

Experts from Indian Institutes of Technology (IITs), National Institute of Hydrology, Indian Institute of Remote Sensing, Indian Institute of Soil and Water Conservation,

State Forest Department of Uttarakhand, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board and NGOs participated in the meeting and deliberated on the project formulation, implementation and identification of the opportunities and constraints in making the Yamuna

Addressing the gathering, the FRI director AS Rawat informed the participants about efforts to be made in the direction of making the Yamuna clean. He also spoke about the various polluting activities around the Yamuna

Speaking at the meet, the



ICFRE deputy director general (Research) SD Sharma informed that the council had been assigned task of rejuvenation of nine major rivers of India by incorporating various new technologies by the Government of India. He said that the detailed

project report of Yamuna rejuvenation through forestry interventions will be prepared by March 2020. Addressing the gathering, Uttarakhand Forest Development Corporation managing director Monish Mullick mentioned the details

preparation of the detailed project report for Yamuna.

Various experts expressed their views on cleaning Yamuna in the technical sessions. These technical sessions were held on experiences from

of forestry interventions in Ganga cleaning efforts and future possibilities, forestry interventions, community participation models, stakeholder consultation, technology usage and criteria identification of GIS layers in addition to a panel discussion.

TIMES OF INDIA 6 JULY, 2019

FRI in Dehradun to revive 'almost dead' Yamuna by 2025

Shivani.Azad@timesgroup.com

Haridwar: After Namami Gange in 2014, the Union government has now set its sights on cleaning the Yamuna. The Forest Research Institute (FRI) in Dehradun has been tasked with reviving the river that once brimmed with life but is practically dead now. FRI scientists — who aim to revive the river by 2025 — told TOI on Friday that the biggest challenge would be to give it a facelift in Delhi and Haryana where it is contaminated with raw sewage and toxic waste.

The Yamuna originates from the Yamunotri glacier. With its total flow length of 1,376 km, it travels through a number of historical cities including Allahabad where it merges into the Ganga. Experts said that the river was in its "most severe state" in the national capital and adjoining areas and reviving its water quality and quantity would be a major challenge. After a preliminary survey, a technical team has earmarked a 500km segment of the river that runs from Delhi to UP and passes via Haryana as the area of prime focus and attention.

Dinesh Kumar, a senior scientist at FRI, said, "The most challenging would be the 22 km patch of Yamuna that runs from Wazirabad Barrage to Okhla Barrage in Delhi where the river has been reduced to a drain. The stretch of the river from Ok-

A S Rawat, director of FRI, said that anthropological pressure and pressure from irrigation had pushed the river into its present state

hla Barrage to Chambal confluence in UP is devoid of oxygen, rendering the river dead, and would be another challenge to overcome."

Director of FRI, A S Rawat, said that anthropological pressure and pressure from irrigation had pushed the river into its present state. "Since independence, the population in the Yamuna basin has increased by 3.5 times. Currently, the irrigated area in the basin is twice of what it was in 1950."

Pollution control boards of respective states would work in tandem with the FRI. The action plan has divided Yamuna into five segments: 172km-long 'Himalayan segment' from Yamunotri glacier in Uttarkashi to Tajewala Barrage; a 224km-long 'upper segment' from Tajewala to Wazirabad Barrage; 22km-long 'Delhi segment' from Wazirabad Barrage to Okhla Barrage; a 490km-long 'eutriphicated segment' from Okhla barrage to Chambal confluence; and a 468km-long 'diluted segment' from Chambal confluence to Ganga confluence.